GOVERNMENT OF INDIA /BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS /RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-V/98
No.PC-V/98/1/6/4

RBE No.162/98
New Delhi, dated 17 -7-98.

The General Managers/CAO(R)/OSDs,
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: Fixation of pay on promotion where lower and promotional grades have been merged and replaced by a single scale of pay.

1. The Railway services (Revised Pay) Rules 1997, have come into force w.e.f. 01.01.1996. The date of notification of the Revised Pay Rules is 08.10.1997. In the revised set up, there are instances where two or more grades have been merged to allot a common revised scale.

2. A question has arisen as to how the fixation of pay is to be done for a person who was promoted from a lower pre-revised scale to a higher pre-revised scale between 01.01.96 (the date of effect of revised pay scales) and 08.10.97 (the date of notification of the Revised pay Rules), in cases where the two scales have been merged into a single revised scale.

3. In this connection it is clarified that since the two scales have been merged w.e.f. 01.01.96, promotions taking place, from the lower scale to the higher scale, between 01.01.96 to 08.10.97 stand nullified. The question as to the extent of protection that may be allowed in such cases has been examined and it has been decided that it is not correct in principle to allow a person any option to retain the pre-revised scale of pay in respect of a post to which he was not actually appointed on or before 01.01.96 and which ceased to exist after that date.

4. In terms of provisions contained in Rule 5 of RSRP Rules, 1997 a Railway servant has the option to retain the existing scale i.e. the scale of the post held by him on 1st January, 1996 until the date on which he earns his next or any subsequent increment in that scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale. The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after 01.01.96, whether for the first time in Government service, or by transfer or promotion from another post. Accordingly all persons recruited after 01.01.96 or appointed by transfer or promotion to posts after that date, should be allowed pay only in the revised scales as admissible under the Railway Services (Revised Pay) Rule 1997. Fixation of pay under Rule 7 of the RSRP Rules 1997 is admissible only either on 01.01.96 or the date of next or any subsequent increment in respect of post held in the pre-revised scale as on 31.12.1995.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं॰पीसी-5/98/आई/6/4
अं॰ नि॰ पी॰सी॰ 5/98

आर॰बी॰ई॰सं॰ 162/98

नयी दिल्ली, दि0 17·7·98

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)/विशेष कार्याधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:-उन मामलों में जहां निचले तथा पदोन्नति वाले ग्रेडों को मिला दिया गया हो तथा इसे एक ही वेतनमान से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, पदोन्नति किए जाने पर वेतन का निर्धारण

1· रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997, 1·1·1996 से लागू हुआ· संशोधित वेतन नियम की अधिसूचना की तारीख 8·10·1997 है· इस संशोधित स्थिति में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां दो अथवा इससे अधिक ग्रेडों को आपस में मिला दिया गया है, ताकि एक सामान्य संशोधित वेतनमान का आबंटन किया जा सके·

2· एक प्रश्न यह उठाया गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के वेतन का निर्धारण किस प्रकार किया जाए जो 1·1·96 (संशोधित वेतनमान लागू किए जाने की तारीख) तथा 8·10·97 (संशोधित वेतन नियम की अधिसूचना की तारीख) के बीच निचले पूर्व-संशोधित वेतनमान से उच्चतर पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदोन्नत हुए थे जबकि इन दोनों वेतनमानों को एक ही संशोधित वेतनमान में मिला दिया गया हो·

3· इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि ये दो वेतनमान 1·1·96 से एक साथ मिलाए गए हैं, अतः 1·1·96 से 8·10·97 के बीच निचले वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में होने वाली पदोन्नति को रद्द समझा जाए· इस प्रकार के मामलों में अनुमति दिए जा सकने वाले संरक्षण की सीमा के संबंध में प्रश्न को जांच की गई है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पद के संबंध में, जिस पर उसकी 1·1·96 को या इससे पूर्व वास्तविक रूप से नियुक्ति न की गई हो तथा जो उस तारीख के बाद समाप्त कर दिया गया हो, पूर्व संशोधित वेतनमान में बने रहने हेतु विकल्प देने की अनुमति देना सिद्धांततः ठीक नहीं है·

4· रेल सेवा संशोधित वेतन नियम 1997 के नियम 5 में अंतर्विष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार किसी रेल कर्मचारी को मौजूदा वेतनमान, अर्थात् 1 जनवरी 1996 को उसके द्वारा धारित पद के वेतनमान में तब तक बने रहने का विकल्प होता है, जब तक कि वह अपनी अगली वेतनवृद्धि अथवा

S.No. PC-[illegible]. Dt: 17-7-98.

5. In such cases, the fixation of pay done as on 01.01.1996 in reference to the pre-promotional grade will be final. However, in order to mitigate the adverse effect of retrospective application of the rules, resulting in drop in emoluments in the types of cases referred to in para 2 above, the President is pleased to decide that in such cases the emoluments drawn against the promotional post in the pre-revised set-up may be protected, if there is loss, in the form of personal pay to be absorbed in future increases of pay in the revised scale.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

7. Hindi version is enclosed.

(NEERA KHANTIA)
Director, Pay Commission
Railway Board.

No.PC-[illegible]/6/4 New Delhi, dated 17-7-98.

Copy to :-

AIRAI (Railways), Mathura Road, New Delhi (with 40 spares)

for Financial Commissioner

Copy forwarded to :-

1. [illegible] N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. [illegible] Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. [illegible] Lucknow
4. [illegible] & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. [illegible] & CAO, CORMOW/New Delhi
6. [illegible] & CAO, CORE/Allahabad
7. [illegible] Civil College/Vadodara
8. [illegible] (RD)/Mumbai
9. [illegible] (Railways), RITES/Chennai
10. [illegible] CAO/CLW/Gwalior-474020
11. [illegible] Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. [illegible] Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS
13. [illegible] Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. [illegible] Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji [illegible] /New Delhi
15. [illegible] Railways/Calcutta
16. [illegible] RDSO, Lucknow
17. [illegible] Ministry of Defence
18. [illegible] 3, Koila Ghat Street/Calcutta
19. [illegible] of Railways, Dhanbad, Bihar
20. [illegible] Secretariat/New Delhi
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible] Moradabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, [illegible] Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Pune, Secunderabad and Trivandrum
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible] & Assistant Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
27. [illegible] Secretary, DRA/New Delhi
28. [illegible] Railway Safety/Lucknow
29. [illegible] Railway Adviser, Embassy of India, Daumenstrasse -7/Bonn
30. [illegible] Officer, V CC, Zonal Railways/PUs/RDSO/Trg. Institutes/Metro Railway/COMOW/CORE/RSC etc.
31. [illegible] Bhawan, Indian Red Cross Market/Delhi
32. [illegible] Officer, CAO(C), S.E. Railway, Bilaspur-495004 (M.P.)
33. [illegible] Rail Bhawan

(Neera Khantia)
Director Pay Commission

उ॰ रे॰ प॰ सं॰ 5/98.

नई दिल्ली, 17.4.98.

उसी वेतनमान में कोई बाद वाली वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं कर लेता अथवा जब तक अपना पद छोड़ नहीं देता अथवा उस वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बंद न कर देता हो॰ उपर्युक्त विकल्प 1॰1॰96 को अथवा इसके बाद किसी पद पर नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा, भले ही उसकी सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्ति हुई हो अथवा वह किसी अन्य पद से स्थानांतरण पर या पदोन्नति होने पर आया हो॰ तदनुसार 1॰1॰96 के बाद भर्ती हुए अथवा उस तारीख के बाद पदों पर स्थानांतरण अथवा पदोन्नति होने पर नियुक्त होने वाले सभी व्यक्तियों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997 के अंतर्गत यथास्वीकार्य संशोधित वेतनमानों में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए॰ रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1997 के नियम 7 के अंतर्गत वेतन का निर्धारण केवल या तो 1॰1॰96 को अथवा 31॰12॰1995 को पूर्व संशोधित वेतनमान में धारित पद के संबंध में अगली वेतनवृद्धि अथवा कोई बाद वाली वेतनवृद्धि के लिए स्वीकार्य है॰

5॰ इस प्रकार के मामलों में पदोन्नति पूर्व वाले ग्रेड के संदर्भ में 1॰1॰1996 को किया गया वेतन का निर्धारण अंतिम होगा॰ बहरहाल, वेतनमानों के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त पैरा-2 में संदर्भित किस्म के मामलों में परिलब्धियों में कमी होती हो, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि इस तरह के मामलों में पूर्व संशोधित स्थिति में पदोन्नति वाले पद के तहत प्राप्त की जाने वाली परिलब्धियों का बचाव किया जाए॰ यदि इससे किसी प्रकार की हानि होती हो तो उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में जो भविष्य में समाहन योग्य हो, वेतन बढ़ाकर संशोधित वेतनमान में वेतन का बचाव किया जाए॰

(नीरा सुटिया)
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड